

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 01 दिसम्बर, 2015

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में "हरित ऊर्जा उपकर विधेयक-2014" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक-2014 हेतु जारी अधिसूचना सं०-342/XXXVI(3)/2015/79/2014 दि०-03-01-2015 जिसका क्रियान्वयन प्रदेश में दिनांक 01-07-2015 से प्रारम्भ हो गया है, को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से मा० राज्यपाल निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत ऐसी ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है एवं राज्य के बाहर पारेषित की जाती है, के उत्पादकों से पारेषित ऊर्जा पर उपकर प्राप्त किया जायेगा जिसकी दर 10 पैसे प्रति यूनिट होगी। ऐसी ऊर्जा पर उपकर का अधिरोपण निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
2. राज्य के वाणिज्य एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा उपकर अधिरोपण किया जायेगा, जो 01 जुलाई 2015 से वसूल किया जायेगा। इस उपकर की राशि यू०पी०सी०एल० द्वारा संग्रहीत कर प्रत्येक वर्ष के 30 जून अथवा इससे पूर्व "हरित ऊर्जा निधि" में लेखाशीर्षक 0801-ऊर्जा-01-जल विद्युत उत्पादन-800-अन्य प्राप्तियां-03-हरित ऊर्जा निधि में प्राप्तियां के नाम से जमा की जायेगी।
3. हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम-2014 के अन्तर्गत "हरित ऊर्जा निधि" के नाम से लेखाशीर्षक 0801-ऊर्जा-01-जल विद्युत उत्पादन-800-अन्य प्राप्तियां-03-हरित ऊर्जा निधि में प्राप्तियां में निधि की स्थापना की जायेगी। इस निधि में 10 पैसे प्रति दर यूनिट तक हरित ऊर्जा उपकर राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर यू०पी०सी०एल० द्वारा अधिरोपण कर जमा कराई जायेगी।

इसके अतिरिक्त ऐसी ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है एवं राज्य के बाहर पारेषित की जाती है, पर उत्पादकों से वसूल कर उपकर निदेशक, उरेडा द्वारा अधिरोपित कर निधि में जमा कराया जायेगा।

4. अधिनियम के उद्देश्य हेतु अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण "उरेडा" उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम-2014 के लिये नोडल एजेंसी नामित की जाती है।
5. निदेशक, उरेडा निरीक्षक एवं निर्धारक प्राधिकारी होंगे जो अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर कार्यों का निष्पादन करेंगे तथा निदेशक, उरेडा को उनकी सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित एवं नियुक्त करने का प्राधिकार होगा।
6. अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत निदेशक, उरेडा निरीक्षक या उप-प्राधिकारी होंगे जो पुस्तकों या अभिलेखों, जो अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकरणों या राशि अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो, का सत्यापन कर सकते हैं एवं ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जहां निम्नलिखित उद्देश्यों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किये जाने का विनिश्चय कर लिया गया हो :-
- रखी गई लेखा पुस्तकों में दिये विवरण और जमा की गई विद्युत की सत्यापन।
 - निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनल्स का बढाना और परीक्षण करवाना।
 - उपकरण के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।
 - ऐसी शक्ति का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों का उद्देश्य पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

अधिनियम की धारा-19(1) के अधीन उत्तराखण्ड शासन में नियुक्त प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा/वैकल्पिक ऊर्जा, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत प्रदाय उपकरण/ब्याज/जुमाने के विरुद्ध अपील प्राधिकारी होंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा दि0-28-11-2015 को दी गयी समिति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1203 (2)/1/2015-03/16/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजर देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट कक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रभारी एन0आई0सी0 को उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाईल।



(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव